PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Jagran, Delhi
Tue, 20 Jun 2017, Page 12
Width: 33.09 cms, Height: 21.93 cms, a3r, Ref: 36.2017-06-20.35

30 जून की आधी रात में संसद में घंटे की आवाज से नई कर व्यवस्था का होगा शुभारंभ

आजादी की याद दिलाएगी जीएसटी की दस्तक

नई दिल्ली, प्रेट्र : वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत को खास बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। यह 15 अगस्त, 1947 की आधी रात को मिली आजादी के जश्न की याद दिलाएगा। देश की दो लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था को आकार देने वाली इस नई टैक्स प्रणाली का आगाज संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल से होगा। यह शायद पहला मौका होगा जब सरकार इस गोलाकार हॉल का इस्तेमाल करेगी। 30 जून की आधी रात को घंटे की आवाज के साथ आजादी के बाद सबसे बड़े कर सुधार के आगाज की गूंज सुनाई देगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता होंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी आमंत्रित किया जा रहा है। मुमकिन है कि यह कार्यक्रम 30 जून को रात्रि 11 बजे से शुरू होकर मध्यरात्रि तक चले। पिछली संप्रग सरकार में वित्त मंत्री होते हुए मुखर्जी पहली बार जीएसटी बिल संसद में लाए थे।

सूत्रों ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल के सदस्य कार्यक्रम में अतिथि होंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली के अध्यक्षता वाली इस काउंसिल की केंद्र और राज्य सरकारों को साथ लाने में अहम भूमिका रही है। नई टैक्स प्रणाली कैसे काम करेगी, इसे तय करने के लिए यह 17 बैठकें कर चुकी है।

सूत्रों के मुताबिक, दशकों की मशक्कत के बाद तैयार हुई जीएसटी प्रणाली को पहले विज्ञान भवन से शुरू करने की योजना थी, जहां केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्रियों से बनी जीएसटी काउंसिल की ज्यादातर बैठकें हुई हैं। लेकिन, नई टैक्स व्यवस्था के महत्व को देखते हुए सेंट्रल हॉल को बेहतर विकल्प माना गया।

जीएसटी टैक्सों के मकड़जाल को खत्म करेगा। इसके तहत सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट सहित कई करों को समाहित कर दिया गया है। यह अमेरिका, यूरोप, ब्राजील, मेक्सिको और जापान से अधिक आबादी वाले एक बाजार को तैयार करेगा। यह धीरे-धीरे देश के पूरे व्यापार परिदृश्य को दोबारा आकार देगा। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था को नई प्रणाली कारोबार करने के लिहाज से एक सुगम स्थान बनाएगी।